

## भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में ई-ट्रांसमिशन पर अधस्थगन का वरिोध

### प्रलिमिंस के लयि:

ई-ट्रांसमिशन पर अधस्थगन, विश्व व्यापार संगठन ।

### मेन्स के लयि:

ई-कॉमर्स पर अधस्थगन से संबधति मुद्दे ।

## चर्चा में क्यों?

भारत जून 2022 से शुरू होने वाले **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के 12वें मंत्रसित्रीय सम्मेलन (MC12) में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (ई-ट्रांसमिशन) पर **सीमा शुल्क** को लेकर अधस्थगन का वरिोध करेगा क्योंकि इसके प्रावधान केवल विकसित देशों के पक्ष में हैं ।

- वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में 11वें मंत्रसित्रीय सम्मेलन पर स्थगन को दो वर्ष के लयि बढ़ा दिया गया था । दसिंबर 2019 में हुई सामान्य परिषद की बैठक में सदस्यों ने मौजूदा प्रावधानों को 12वीं मंत्रसित्रीय सम्मेलन तक बनाए रखने पर सहमतजिताई थी ।

## ई-ट्रांसमिशन पर अधस्थगन:

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश **वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा अधस्थगन पर सहमत हुए थे** और स्थगन की अवधको समय-समय पर मंत्रसित्रीय सम्मेलनों में बढ़ाया जाता रहा है, जो कि 164 सदस्यीय संगठन (WTO) का सर्वोच्च नरिणय लेने वाला नकियाय है ।
  - यह स्थगन फोटोग्राफिक फलिमें, सनिमैटोग्राफिक फलिमें, प्रटिड वषिय-वस्तु, संगीत, मीडिया, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसेडजिटल उत्पादों पर लागू है ।
- वर्ष 1998 में दूसरे मंत्रसित्रीय सम्मेलन में मंत्रियों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर घोषणा को अपनाया, जसिमें ई-कॉमर्स पर एक कार्यक्रम का आह्वान कयिा गया था, जसि कुछ वर्ष पश्चात् अपनाया गया था ।
  - चूँकि अधिकांश देशों में ई-कॉमर्स पर मज़बूत नीतियों नहीं थीं, जो 1998 में विकसित देशों में भी व्यापार का एक उभरता हुआ क्षेत्र था, उन्होंने इस पर गहन बातचीत करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के सीमा शुल्क पर रोक लगाने के लयि वरक प्रोग्राम आयोजति करने का नरिणय लयिा था ।
- विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद ने 1998 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक, वतित्तीय और विकास आवश्यकताओं पर वचिार करके वैश्विक ई-कॉमर्स से संबधति सभी व्यापार मुद्दों की व्यापक जाँच करने के लयि ई-कॉमर्स पर वरक प्रोग्राम की स्थापना की ।
  - विश्व व्यापार संगठन वरक प्रोग्राम ई-कॉमर्स को "इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वपिणन, बकिरी या वतिरण" के रूप में परिभाषति करता है ।

## बैठक में भारत की मांग:

- जून 2022 में 12वीं मंत्रसित्रीय सम्मेलन में कई WTO सदस्य 13वीं मंत्रसित्रीय सम्मेलन तक स्थगन के अस्थायी वसितार की मांग पर वचिार कर सकते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस बार इसे और जारी रखा जाए ।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कई अवसरों पर संगठन से इस मुद्दे पर फरि से वचिार करने के लयि कहा है और विकासशील देशों पर स्थगन के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर कयिा है ।
- भारत चाहता है कि विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स क्षेत्र पर वरक प्रोग्राम को तेज़ करे ।
- भारत ने यह भी कहा है कि काउंसलि फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसलि फॉर ट्रेड इन सर्वसिज़, काउंसलि फॉर टरपिस (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबधति पहलू-TRIPS) तथा व्यापार और विकास समति को मूल रूप से नरिधारति अपने संबधति जनादेश के अनुसार ई-कॉमर्स पर चर्चा करनी चाहयिे ।
- भारत का मानना था कि मौजूदा वैश्विक ई-कॉमर्स क्षेत्र की अत्यधिक वषिम प्रकृति और संबधति बहुआयामी मुद्दों के नहितार्थ समझ की कमी को देखते हुए ई-कॉमर्स में नयिमें और वषियों पर डब्ल्यूटीओ में औपचारिक बातचीत शुरू होनी चाहयिे ।

## अधस्थगन से संबंधति मुद्दे:

- भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के आयात में तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, मुख्य रूप से फिलिमों, संगीत, वीडियो गेम और मुद्रति सामग्री जैसे- उपकरण, जनिमें से कुछ स्थगन के दायरे में आ सकते हैं।
- विकासशील देशों के लिये अपनी डिजिटल उन्नति हेतु नीतगित योजनाओं को संरक्षति करने, आयात को वनियमति करने और सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिये अधस्थगन की अनुमति देना महत्त्वपूर्ण है।
- विकासशील देशों को संभावति टैरफि राजस्व हानि वार्षिक 10 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- जबकि डिजिटल अभिक्रितीओं का मुनाफा और राजस्व लगातार बढ़ रहा है, इन आयातों की जाँच करने तथा अतरिक्रिती टैरफि राजस्व उत्पन्न करने की सरकारों की क्षमता ई-कॉमर्स पर स्थगन के कारण 'गंभीर रूप से' सीमति हो रही है।
- इसका प्रभाव वनिरिमाण में 3डी प्रटिगि जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग और अन्य करतव्यों एवं शुल्कों के नुकसान व औद्योगीकरण पर पड़ेगा।

## आगे की राह

- विकासशील देशों को डिजिटल क्षेत्र में वकिसति देशों के साथ तालमेल बठाने के लिये नीतियों को लागू करने में लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- विकासशील देशों के लिये फिलिमों, संगीत और वीडियो गेम जैसे अपने लक्ष्यी आयात को वनियमति करना अत्यंत आवश्यक है। अधस्थगन को हटाने से सरकारों को नीतगित लाभ मलिया।

## वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत में माल के भौगोलिक संकेत (रजसिटरेशन और संरक्षण) अधनियम, 1999 को नमिनलखिति में से कसिसे संबंधति दायतिवों के अनुपालन के लिये लागू कया गया?

- (a) आईएलओ
- (b) आईएमएफ
- (c) यूएनसीटीएडी
- (d) डब्ल्यूटीओ

उत्तर: D

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture)' एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनटिरी एंड फाइटोसैनटिरी मेज़र्स (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) और 'पीस क्लॉज (Peace Clause)' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं?

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: C

## स्रोत: द हट्टू